

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

- भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषण के आधार पर राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना का प्रारम्भ प्रदेश में वर्ष 1981-82 में हुआ।
- यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रतिवर्ष चलाया जाता है।
- बायोगैस संयंत्रों का निर्माण के लिए अनुदान की व्यवस्था वर्ष 2014-15 में निम्नानुसार भारत सरकार द्वारा की गयी है:-

क्रमांक	संयंत्र की क्षमता/मद	अनुदान की राशि (रु०)
1	1 घ०मी०	सामान्य - 5500/- एससी/एसटी-7000/-
2	2, 3, 4, 6 घ०मी०	सामान्य - 9000/- एससी/एसटी-11000/-
3	शौचालय युक्त संयंत्र	रु० 1200/-अतिरिक्त
4	टर्नकी जॉब फीस	रु० 1500/-प्रति संयंत्र

- यह एक ऐसी विधि है जिससे उत्पन्न गैसीय उत्पादों को घरेलू उपयोग यथा खाना पकाने, रोशनी आदि के लिये किया जाता है।
- इसके प्रयोग से लकड़ी के ईंधन की बचत होती है साथ ही रसोई में धुआं न उत्पन्न होने के कारण महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा होती है।
- यह कार्बनिक खाद उत्पन्न करता है, जिससे कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलती है।
- अनुश्रवण- योजना की प्रगति का आनलाइन अनुश्रवण विभाग की वेबसाइट-rd.up.nic.in के माध्यम से किया जाता है
